लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 अप्रैल 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -15

"विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए, जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
: महात्मा गांधी

पानी है अनमोल, इसे व्यर्थ न बहाएं 3

जैविक गेहूं : बंपर पैदावार, मुनाफ़ा अधिक 5

आस्था का मेला 8

चहुंमुखी विकास के लिए करोड़ों की सौग़ात

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर अपनी सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, खेल, बिजली आदि से जुड़ी 1,411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों में 163 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 475 करोड़ रुपए की लागत वाली 80 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 935 करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं।

उन्होंने संदेश दिया है कि सरकार प्रदेश के समुचित व सभी क्षेत्रों का एक समान विकास की नीति पर चल रही है। इन सौग़ातों से हरियाणा विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय के भाव के साथ वे पिछले छह वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य है।

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचकूला के विकास के लिये अनेक सौगात दी है जो विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। पंचकूला में फिल्म सिटी बनने से पंचकूला न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान स्थापित करेगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकारों के यहां आने से न केवल होटल इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा, बल्कि युवाओं के लिये रोज़गार के अनेक अवसर पैदा होंगे।

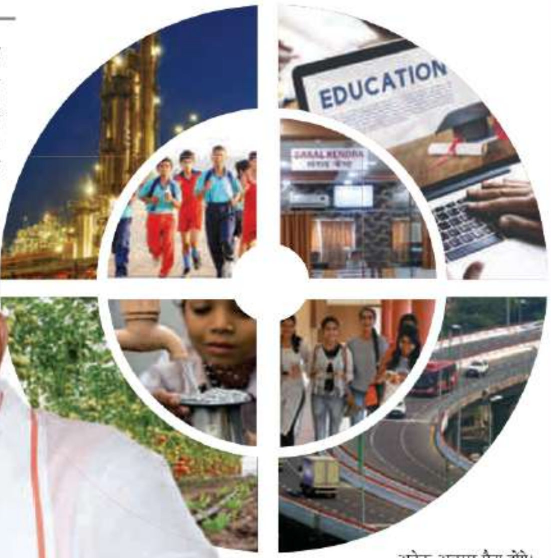

कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी हलकों में समान रूप से विकास कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी संपर्क मार्गों को पक्का किया जाएगा, इसमें छह करम तक के रास्ते लोक निर्माण विभाग, पांच करम तक के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड तथा पांच करम से कम रास्तों को ग्राम पंचायतों द्वारा पक्का किया जाएगा।

छह विधेयक पारित

विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन छह विधेयक पारित हुए। इनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम में संशोधन करने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक तथा मार्च, बीते वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग विधेयक शामिल हैं।

संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो होगी वसूली

आंदोलन के नाम पर किसी भी जनसमूह द्वारा सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब अपराध की श्रेणी में होगा। नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान होगी तथा उन्हें क्षति का जिम्मेवार माना जाएगा। लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया है। यह विधेयक सम्पति को नुकसान पहुंचाने वालों की जिम्मेदारी को निर्धारित करने के साथ-साथ पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाना भी सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विधानसभा बजट सत्र की समाप्ति के उपरांत बातचीत में कहा कि संपत्ति चाहे निजी हो या सरकारी, उसे सुरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है। सम्पति के नुकसान से किसी को भी फायदा नहीं होता, बल्कि संपत्ति की क्षति होने से सबका नुकसान होता है।

राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक अमृत-महोत्सव

देश की स्वतंत्रता के 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले 'अमृत-महोत्सव' की हरियाणा सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग लेकर निर्देश दिए कि करीब 17 माह तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सभी विभागों द्वारा ऐसे अनुकरणीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें देश की आजादी से लेकर वर्तमान समय तक के विकास के सफ़र की झलक दिखाई दे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अमृत-महोत्सव' का शुभारंभ करते हुए गत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती से दांडी-मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसी दिन एक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इस महोत्सव की हरियाणा में भी शुरुआत की।

वीर-शहीदों की बनेगी डॉक्यूमेंट्री

आजादी से लेकर आज तक राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा या देश में शांति की स्थापना बनाए रखने में भूमिका निभाने वाले सेना व अर्ध-सैनिक बल के वीर-शहीदों की जीवन-यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर विभिन्न समारोह या कार्यक्रमों में प्रदर्शित करने तथा स्मारिका प्रकाशित करने की योजना है ताकि प्रदेश की युवा पीढ़ी उनके शौर्य एवं बलिदान से प्रेरणा ले सके। विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनके जीवन-संघर्ष पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई जाने पर भी चर्चा हुई है।

महोत्सव में लोगों की भागीदारी

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता व देशभक्ति के विषयों को लेकर निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, गीत प्रतियोगिता आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। सुझाव दिया कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'आत्मनिर्भर भारत' समेत अन्य विशेष अभियानों में जहां 'अमृत-महोत्सव' को केंद्र में रखकर कार्यक्रम किए जाएं, वहीं हिपा के ट्रेनिंग कोर्स में भी 'अमृत-महोत्सव' की कैप्सूल-क्लास लगाई जाए।

संपादकीय

प्यास और पानी

पानी चाहे आंख का हो या जलाशय का या फिर नदी का, पानी सूखना नहीं चाहिए। यूं तो पानी 'बोझीला' नहीं होता, पर आंख से निकल जाए तो मन बहुत 'हल्का' हो जाता है। तभी रहीम याद दिलाते थे-

'रहिमन पानी राखिए/बिन पानी सब सून/'

मगर संतों की बातें कौन सुनता है। पानी का संकट हर रोज थोड़ा-थोड़ा गहरा होता है, मगर कहां फुर्सत है हमें इस संकट से जूझने की। पानी, आज भी किसान का, गांव का, वन्य प्राणियों का, खेतों की बालियों का, धान का, गेहूं का, परिंदों का, सबका सांझा मुद्दा है। मगर हमें प्रदर्शनों, धरनों, बयानों से फुर्सत कहां।

चलिए जो बात हम हाशिए पर सरकाते हैं, उसे एक प्रख्यात शायर डॉ. राही मासूम 'रज़ा' के माध्यम से समझने का प्रयास करें।

रज़ा की एक नज़्म है- प्यास और पानी
मैंने जब भी जन्म लिया है
अपने को तन्हा पाया है
अपने को प्यासा पाया है।
पानी-पानी!
इस नन्हे से लफ़्ज़ में कितनी मौसीक़ी है
पानी-पानी/प्यास और पानी
मैंने जब भी जन्म लिया है
इन लफ़्ज़ों पर ग़ौर किया है
पानी क्या है?
प्यास अज़ल है
प्यास अबद है
बीच में रेत का एक सागर है
लम्हे शबनम के क़तरे हैं
होंठों तक आने से पहले उड़ जाते हैं
मैंने जब भी जन्म लिया है
लम्हों के उन क़तरों के पीछे भागा हूं
लेकिन मैं अब तक प्यासा हूं
प्यास अज़ल है
प्यास अबद है/
बीच में रेत का इक सागर है
इस सागर का नाम तमन्ना या फिर शायद
क़ैद-ए-हयात-ओ-बन्द-ए-ग़म है
प्यास के इस तपते सहरा में सैराबी को ढूंढने वाले
खो जाते हैं/सब दीवाने हो जाते हैं
धूप के इस काले सहरा में सब तन्हा हैं
हद्दे-नज़र तक अपनी परछाई के अलावा
कोई नहीं है/कोई नहीं है
कोई नहीं है/इक अंगारा है कि ज़मीं है
साये का इक हल्का-सा धब्बा भी नहीं है
जिसकी गोद में बैठ के कोई घास की उंगली से
शबनम के क़तरे चाटे
माथा पोंछे/दामन झाड़े/और ये सोचे
लम्हों के सहरा में अब तक कितना पसीना और
आंसू के कितने/क़तरे खर्च हुए हैं
मैंने जब भी जन्म लिया है
इन बातों पर ग़ौर किया है/आंसू क्या है?
ग़म की आग में पिघली हुई शख़्सीयत है जो
क़तरा-क़तरा बह जाती है
इस जीने के हाथों हम क्या-क्या सहते हैं
अपनी प्यास बुझाने को हम
खुद आंसू बनकर बहते हैं
प्यास अज़ल है/प्यास अबद है
प्यास के इस गहरे सागर में सैराबी को ढूंढने वाले
खो जाते हैं, इस सागर का नाम कन्हैया
डूबने वाली, जमुना तट पर रहने वाली
गोकुल की एक पगली राधा
जमुना तट से दूर कोई दीवानी 'मीरा'
इकतारे की तार-सी तन्हा
खुद सागर भी बंसी के मीठे झरने से चुल्लू भरकर
मौसीक़ी पीता रहता है
सागर ख़ुद कितना प्यासा है!
सागर ख़ुद कितना तन्हा है!

- डा चंद्र त्रिखा

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरु की जा रही है। योजना के तहत सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें गरीबी रेखा से उबारते हुए मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा।

ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8000 से 9000 मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी तथा बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

राज्य स्तर पर परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक 65 लाख परिवारों में से करीब 55 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों के उत्थान को सरकार का हर विभाग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राथमिकता देगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 में इस अभियान के तहत दो लाख परिवारों के उत्थान का प्रस्ताव है। सरकार की नीति इन परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी के अंतिम पायदान पर अनिवार्य रूप से कवर करने की है। इसके बाद अगले एक लाख परिवारों की पहचान कर उनके स्थाई रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसमें समाज के सभी वर्गों के परिवारों लाभ मिलेगा।

आवास नवीनीकरण योजना

मुख्यमंत्री ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80 हजार रुपए की है।

काबिलेजिक्र है कि अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था।

वार्षिक आय स्लैब

गरीब परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उनकी आय संबंधी नियमों में ढील दी है। एक अप्रैल, 2021 से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को 1 लाख 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपए किया गया है। इसके अलावा सामाजिक उत्पीड़न के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है।

विचार सम्मान एवं प्रसार योजना

मुख्यमंत्री की ओर से महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तिय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

विवाह शगुन योजना

वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभपात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है।

प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग

राज्य सरकार 2 लाख 50 हजार रुपए तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एचटीईटी, सीजीएल, एनईईटी व जेईई इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है।

-संवाद ब्यूरो

संपत्ति के तत्काल पंजीकरण की सुविधा

हरियाणा सरकार ने राज्यभर में अपनी आधुनिकीकृत तहसीलों में डीड के पंजीकरण के लिए 'तत्काल डीड-अपॉइंटमेंट सेवा' की एक नई विशेष शुरुआत की है। इस सेवा के चालू होने से अब प्रदेश के नागरिकों को अपनी संपत्ति को तत्काल आधार पर पंजीकृत करवाने की सुविधा प्राप्त होगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इस सेवा के तहत लोगों के लिए तत्काल आधार पर डीड रेजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेने का प्रावधान किया गया है। कौशल ने कहा कि इस सेवा का उपयोग करके आवेदक ई-चालान के रूप में 25,000 रुपए के तत्काल शुल्क का भुगतान करके डीड पंजीकरण के लिए ऑनलाइन तत्काल अपॉइंटमेंट ले सकता है।

तत्काल अपॉइंटमेंट केवल पंजीकरण के दिन प्रातः 8 बजे से बुक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में 100 सामान्य अपॉइंटमेंट स्लॉट के अलावा 10 अपॉइंटमेंट स्लॉट तत्काल सेवा के लिए आरक्षित किये गये हैं। तत्काल अपॉइंटमेंट बुक करने के विभिन्न चरणों बारे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि आवेदक को egrashry.nic.in पोर्टल पर जाना होगा और तत्काल अपॉइंटमेंट सर्विस चार्ज के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करने होंगे और ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि का उपयोग करके 25,000 रुपए की राशि का भुगतान करने उपरांत ई-चालान बनेगा। इसके उपरांत jamabandi.nic.in पोर्टल पर जाकर डीड अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

भोपाल सिंह एचएसएससी के अध्यक्ष नियुक्त

हरियाणा सरकार ने भोपाल सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। कंवल जीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन को एचएसएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

नवनियुक्त चेयरमैन भोपाल सिंह एक सामान्य और साधारण किसान परिवार से आते हैं। भोपाल सिंह उच्च शिक्षित और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। वे आठ विषयों में एमए के साथ-साथ विधि स्नातक भी हैं। वह केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के सचिव भी रह चुके हैं। वह आज भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमए (लोक प्रशासन) के विद्यार्थी हैं। भोपाल सिंह ने हिंदी, अंग्रेजी, पत्रकारिता, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान समेत आठ विषयों में एमए की है।

मोदी ने की थी तारीफ़

पिछले साल अपने इकलौते बेटे की शादी में मात्र एक रुपया शगुन लेने के कारण भोपाल सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। उनकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। भोपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से युवाओं को बार-बार रजिस्ट्रेशन कराने और फीस भरने से निजात मिलेगी। साथ ही अधिक से अधिक प्रार्थी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे।

हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।

परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत किए 60 लाख परिवारों में से सर्वे करवाया जाएगा और पहले चरण में सबसे न्यूनतम आय वाले एक लाख परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें स्वरोज़गार देने की योजना तैयार की जाएगी।

पानी है अनमोल इसे व्यर्थ न बहाएं

मनोज प्रभाकर

मैदानी इलाकों में जल की उपलब्धता ठीक ठाक है, इसका मतलब यह नहीं है कि जल संकट नहीं है। जल संकट है, उस पर चिंता भी जताई जा रही है मगर चिंता इस बात की है आने वाले संकट से खबरदार कोई नहीं है। राजकीय व कुछ अन्य एजेंसियों की ओर से जल संरक्षण पर कार्य हो रहा है लेकिन पानी का अनावश्यक दोहन और उसका दुरुपयोग बराबर हो रहा है। जन मानस केवल वर्तमान के तनिक सुख को देख रहा है, वह यही नहीं सोच पा रहा है कि उनकी इस लापरवाही से आने वाली पीढी के सामने कितना बड़ा सकंट खड़ा हो जाएगा।

गर्मी का मौसम शुरु होते ही पेयजल की किल्लत शुरु हो जाती है पर्वतीय क्षेत्र में पानी की उपलब्धता अपेक्षाकृत बहुत कम है। सिंचाई जल के अभाव की शिकायतें भी सुनने को मिलती है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, पेयजल की आपूर्ति पहले कुओं और तालाबों से होती थी। जैसे जैसे जमीन से पानी निकालने की तकनीक विकसित होती गई पानी का दोहन बढ़ता चला गया। प्रदेश का काफी हिस्सा ऐसा है जहां का भूमिगत जल काफी नीचे चला गया है। इतना ही नहीं जहां पीने का मीठा पानी था वहां खारा हो गया है। बहुत से गांवों में स्थिति है कि भूमिगत जल खारा हो गया है। अब पीने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की पेयजल आपूर्ति या निजी एजेंसी की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

बात पानी के दुरुपयोग की है। सरकार का कार्य जलप्रबंधन तो हो सकता है लेकिन पानी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य तो हर प्रदेशवासी के गौर करने पर ही होगा।

प्रदेश के कृषि क्षेत्र में करीब 7 लाख ट्यूबवैल हैं। इनके अलावा शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिसमें सैंकड़ों की संख्या में सबमर्सिबल न लगे हों। शहरों में तो इनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। अनुमान के मुताबिक प्रति सेकंड लाखों गैलन पानी जमीन से निकाला जा रहा है। खेती में धान की फसल में सर्वाधिक खपत हो रही है। सबमर्सिबल के पानी का इस्तेमाल घरेलू इस्तेमाल के अलावा गलियों की सफाई करना, पशुओं को नहलाना, वाहनों की धुलाई करना, पेड़ पौधों में देना, उद्योग, भवन निर्माण व अन्य कार्यों में धड़ल्ले से हो रहा है। बिना कार्य के भी ये छोटे ट्यूबवैल अनवरत चलते रहते हैं। जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से बिछाई गई पाइप लाइनों से भी अधिकांश गांवों में पानी लीकेज है। घरों के बाहर लगी टोंटी पर पानी बंद करने की व्यवस्था नहीं है। पानी लगातार बह रहा होता है। संबंधित मकान मालिक उसे बंद करने की कतई जहमत नहीं उठाता। स्थानीय पंचायत की ओर से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। पहले जोहड़ तालाब सूख जाते थे लेकिन आज वे निकासी के पानी से लबालब है।

प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए ज्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और पानी का दुरुपयोग रोकना होगा। यह तभी संभव है जब इसमें जन-जन की भागीदारी हो और इसका हमारी आस्था व आत्मा से जुड़ाव हो। आने वाली पीढ़ी के सुख के लिए संकल्प लेना होगा कि पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

चावल के साथ गया पानी

देश में पानी की सबसे ज्यादा खपत कृषि में 83 प्रतिशत, उद्योग में 12 व घरेलू में पांच प्रतिशत होती है। पंजाब व हरियाणा में बहुतायत में धान की खेती होती है। धान में पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में एक किलो धान पैदा करने में 5 हजार लीटर से ज्यादा पानी की खपत होती है। साल 2019-20 में भारत की ओर से करीब 44.15 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया। इतने टन बासमती चावल उगाने के लिए 12 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने 44.15 लाख टन बासमती के साथ 12 ट्रिलियन लीटर पानी भी दूसरे देशों को भेज दिया, जबकि पैसे केवल चावल के मिले।

तालाबों का जीर्णोद्धार

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार व जल शोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को मैचिंग ग्रांट के रूप में 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य तालाब विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा 5 पोंड व 3 पोंड तकनीक से लगभग 200 तालाबों के पानी को उपचारित करने की शुरूआत की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 14000 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना को भी योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। तालाबों के पानी को जैविक विधि से शुद्ध करने की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सोनीपत जिला के जुआ गांव के तालाब के लिए पायलेट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा।

वाटर रीचार्ज वेल

अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में गिरते भूजल को नियंत्रित करने के लिए 1,000 वाटर रीचार्ज वेल स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार ने आठ जल-प्रखंडों रतिया (फतेहाबाद), सीवन और गुहला (कैथल), पिपली, शाहाबाद, बबैन और इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) और सिरसा (सिरसा) में रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जहां भूजल स्तर 40 मीटर से कम है और इन ब्लॉकों में किसानों को ''मेरा पानी - मेरी विरासत'' पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 32.33 करोड़ रुपए होगी। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण के माध्यम से घटते भूजल तल का संरक्षण करना है।

अटल भूजल योजना के तहत अत्यधिक भूजल दोहन व डार्क जोन वाले 13 जिलों के 36 खण्डों की 1895 ग्राम पंचायतों की लगभग 12.55 लाख हैक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा और आगामी पांच वर्षों में इस कार्य पर 723.19 करोड़ रुपए की राशि खर्च की योजना है।

नहरी तंत्र को सुधारने का लक्ष्य

यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानांतर दिल्ली शाखा, संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरोद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। करीब 110 चैनलों के पुनरोद्धार का कार्य जारी है। इसके अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखीदादरी और भिवानी में लिफ्टिंग प्रणाली की क्षमता को सुधारने तथा प्रदेश की सभी टेलों पर पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

फसल चक्र को बदलना होगा

कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. ए.के. सिंह का कहना है कि चावल व गेहू के फसल चक्र को बदलना बहुत जरूरी है ताकि पानी का अधिक से अधिक संरक्षण किया जा सके। प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि किसानों को जीरो टिलेज, लेजर लेवलिंग, बेड प्लांटिंग, सूक्ष्म एवं टपका सिंचाई आदि को अपनाना होगा।

सदा हमें समझाए नानी,
नहीं व्यर्थ बहाओ पानी।
हुआ समाप्त अगर धरा से,
मिट जाएगी ये जिंदगानी।
नहीं उगेगा दाना-दुनका,
हो जायेंगे खेत वीरान।
उपजाऊ जो लगती धरती,
बन जायेगी रेगिस्तान।
हरी-भरी जहां होती धरती,
वहीं आते बादल उपकारी।
खूब गरजते, खूब चमकते,
और करते वर्षा भारी।
हरा-भरा रखो इस जग को,
वृक्ष खूब लगाओ।
पानी है अनमोल रत्न,
एक-एक बूंद बचाओ।

रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। माजरा गांव के लोगों ने एम्स निर्माण के लिए आवश्यक भूमि पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए योजनाबद्ध कालोनी विकसित की जाएंगी, जहां पर बिजली की सुविधा के लिए अलग पावर हाउस होगा तथा उनके पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब भी बनाए जाएंगे।

पंचायतों को सशक्त करने की तैयारी

- पंचायती राज संस्थाओं को 10:15:75 के अनुपात में निधियां, कार्य एवं पदाधिकारी हस्तांतरित करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास।
- पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में आधी महिलाएं होंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 'लाल डोरा' के भीतर रहने वाले निवासियों को टाइटल डीड प्रदान करने की एक योजना राज्य में सफलतापूर्वक शुरू। योजना के तहत लगभग 400 गांवों को पहले ही कवर किया जा चुका है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ की स्थिति और ठोस/तरल कचरा प्रबंधन की स्थिरता निरंतर कायम रखने पर बल दिया जाएगा।
- 66,320 करोड़ रुपए की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन की कुल 1,542 और तरल कचरा प्रबंधन की 1,807 परियोजनाएं स्वीकृत।
- तरल कचरा प्रबंधन की 552 परियोजनाएं भी पूरी।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उभरते बाजार अवसरों तक पहुंच के लिए शहरी फड़ी विक्रेताओं को उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा एवं कौशल की सुविधा का प्रस्ताव।

पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त करने की तैयारी है। राज्य सरकार ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। पीआरआई के सशक्तिकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्तर को बनाए रखने, ठोस कचरा प्रबंधन, ग्रामीण जीवन के मूल्य संवर्धन, ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण अवसंरचना को सुधारने और शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक जीवंत बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बजट 2021-22 में ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 5,980 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 1,755 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग से तथा 4,225 करोड़ रुपए राज्य बजट से प्रस्तावित हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं, जिनमे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, सांसद आदर्श, ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण इत्यादि शामिल है, के कार्यकर्ताओं के साथ जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक अनूठी तकनीकी आधारित पहल-ग्राम दर्शन की गई है। यह किसी ग्राम पंचायत के किसी भी नागरिक को उसकी विकास कार्यों की मांग प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। जन प्रतिनिधि द्वारा विकास कार्यों का अनुमोदन किये जाने पर संबंधित पंचायतीराज संस्था या सरकार एजेंसी धनराशि उपलब्ध होने पर इन कार्यों को करेगी।

वित्तीय शक्तियां बढ़ाई

राज्य सरकार ने पीआरआई को विभिन्न वित्तीय शक्तियां प्रदान करके उनके राजस्व के स्व-संसाधनों को बढ़ाया है। 24 फरवरी, 2021 से ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार भी लगाया गया है। एकत्रित राजस्व का एक प्रतिशत जिला परिषद और पंचायत समिति को दिया जाएगा तथा शेष एक प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। विकास कार्यों के लिए केवल इससे जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को लगभग 400 करोड़ रुपए वार्षिक मिलेंगे। इसी प्रकार, 28 फरवरी, 2021 से बिजली की खपत पर दो प्रतिशत पंचायत कर लगाया गया है और इससे ग्राम पंचायतों को लगभग 100 करोड़ रुपए वार्षिक मिलेंगे।

> सभी पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में आधी महिलाएं होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 'लाल डोरा' के भीतर रहने वाले निवासियों को टाइटल डीड प्रदान करने की एक योजना राज्य में सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जरुरी है ग्राम पंचायत संस्थाओं को मजबूत करना, इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है।
>
> मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

ई-टेंडर प्रक्रिया से विकास कार्य

पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को जिला परिषद के दायरे में लाया गया है ताकि विकास कार्यों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। बस क्यू शेल्टर एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, उप-स्वास्थ्य केंद्रों का रख-रखाव और प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी करने जैसे अन्य कार्यों की जिम्मेवारी जिला परिषद को सौंपी गई है। पीआरआई कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए पांच लाख रुपए से अधिक की अनुमानित लागत के सभी विकास कार्य केवल ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किये जाएंगे।

महिला प्रतिनिधियों को स्कूटी

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में उन 28 महिला पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को स्कूटी भेंट कर सम्मानित किया जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में अमिट छाप छोड़ी है। श्री चौटाला गुरुग्राम व जींद में भी ऐसी दृढ़संकल्पी व कर्मठ 72 महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित कर चुके हैं।

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने व उनमें लीडरशिप का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मैंने पंचायतीराज संस्थाओं में बेहतर कार्य करने वाली 100 महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित करने का सुझाव दिया था। इस बारे में हमने 'हीरो मोटर्स कॉर्प' कंपनी से सीएसआर फंड के तहत ये स्कूटी देने का अनुरोध किया तो कंपनी द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया।

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं में अनुकरणीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों की 'सफलता की कहानी' (सक्सेस स्टोरी) दर्शाने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी ताकि अन्य महिलाएं उनसे प्रेरणा ले सकें।

कृषि एवं सिंचाई पर फोकस

बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा है कि प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर बड़ी संवेदनशीलता के साथ तैयार किया गया है । उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5052 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए थे जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में 6,111 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो 20.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार सिंचाई के लिए पिछले वर्ष के संशोधन अनुमान 2892 करोड़ रुपए के थे। इस वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में इसे बढ़ाकर 5081 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत की वृद्धि है। सिंचाई का पैसा पश्चिमी यमुना नहर के हथनीकुंड बैराज से भालौठ ब्रांच तक जीर्णोद्धार पर खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार, सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।

प्रोपर्टी टैक्स नहीं लगेगा

हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रोपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। सम्पत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

एन्हांसमेंट सेटलमेंट स्कीम 30 अप्रैल तक

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में एन्हांसमेंट के लिए 3 मार्च, 2021 से जारी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम 30 अप्रैल, 2021 तक जारी रहेगी। अब तक इस योजना के तहत 762 प्लाटधारकों को 31.10 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है, जबकि अभी तक प्लाटधारको द्वारा 19.74 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं।

योजना के तहत 15430 प्लाटधारकों का 823 करोड़ रुपए का एन्हांसमेंट सेटलमेंट होगा, जिसके तहत 20 से 80 प्रतिशत तक लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 15 मई, 2018 को जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई तो लगभग 60 हजार डिफाल्टर थे। 16 जुलाई, 2018 तक जारी इस स्कीम में 24,163 लोगों को 40 प्रतिशत की दर से 568 करोड़ रुपए का रिबेट दिया गया है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के तहत पहली नवम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक 37.50 प्रतिशत की दर से 4027 लोगों को 93 करोड़ रुपए की रिबेट दी गई।

पहली अप्रैल, 2021 से देश में जनगणना शुरू की जाएगी, इस दौरान जो भी गरीब लोगों के लिए मकानों व उपलब्ध ज़मीन का डाटा उपलब्ध होगा, उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा आगे कोई विचार किया जा सकता है।

सभी सुविधाओं से युक्त प्रदेश का पहला साइक्लिंग वेलोड्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनाया जायेगा। इस साइक्लिंग वेलोड्रम से खेलों की बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं करवाई जा सकेंगी और इनका लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा।

'औषधीय पौधों की खेती पर ध्यान दें किसान'

कोरोना महामारी से बचाव के लिए औषधीय पौधों की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि वर्तमान की विषम परिस्थितियों में औषधीय पौधों की वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक महत्ता बढ़ रही है। इसलिए फसल विविधिकरण में भी औषधीय पौधों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे किसानों को आमदनी में भी इज़ाफा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। इसलिए लोगों को प्राचीन आयुर्वेद पद्धति की ओर फिर से लौटना होगा। उन्होंने किसानों से भी गुणवत्तापूर्वक औषधीय पौधों की खेती को अपनाने का आह्वान किया, क्योंकि इनकी वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक मांग है। ऐसा करने से किसानों की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी औषधीय फसलों और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की है। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने अनुभाग के वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तक 'मेडिसनल गार्डन एट ए ग्लांस' का भी विमोचन किया।

घर में भी लगाएं औषधीय पौधे

हिसार से आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. सुखवीर वर्मा ने कहा कि हमारे जीवन में घर की रसोई से लेकर अन्य सभी ज़रूरत की जगहों पर आयुर्वेद का बहुत महत्त्व है। उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों के निदान में औषधीय जड़ी-बुटियों के उपयोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने अपने घरों में तुलसी, एलोवीरा, अश्वगंधा, गिलोय जैसे औषधीय पौधों को लगाने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ. बी.आर. कंबोज ने औषधीय पौधों को फसल विविधिकरण के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान कम ऊपजाऊ व कम सिंचित क्षेत्रों में भी औषधीय पौधों की खेती को आसानी से कर सकते हैं।

इस दौरान कैंपस स्कूल की छात्रा पूर्वा शर्मा ने औषधीय पौधों की उपयोग संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. छाबड़ा ने कहा कि भारत विश्व में औषधीय पौधों में दूसरे स्थान पर है। प्रत्येक पौधे में औषधीय गुण मौजूद होते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं उठा पाते। भविष्य में हर पौधा अपनी अलग पहचान बनाएगा। हमें औषधीय पौधों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाना है।

-संवाद ब्यूरो

आक्सीजन बाग

सोनीपत जिले के गांव भटगांव में आक्सीजन बाग लगाया जा रहा है। प्रदेश में यह दसवां आक्सीजन बाग होगा। दस एकड़ में फैले इस बाग में एक सौ से ज्यादा प्रजातियों के औषधिय व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। बाग के बीच एक कच्चा तालाब होगा जिसमें पक्षी पानी पी सकेंगे। ट्रीमैन कहे जाने वाले देवेंद्र सुरा यह बाग लगा रहे हैं। देवेंद्र गांव गांव जाकर पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भटगांव में दादा कराऊ की जमीन पर यह बाग तैयार हो रहा है। गांव के प्रत्येक घर से इस बाग में पौधारोपण किया जाएगा। पौधे की देखरेख की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होगी।

देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में पर्यावरण मित्रों की टीम बनाई है। टीम में दस हजार से ज यादा सदस्य हैं। ये सभी पर्यावरण मित्र न केवल अपने बल्कि अन्य गांवों में जाकर भी पौधारोपण कर रहे हैं। कई गांव में आक्सीजन बाग लगाने की तैयारी चल रही है। सोनीपत के सेक्टर 23 में हजारों पौधे लगाकर बाग तैयार किया गया है। गोहाना रोड स्थित गांव बीधल में सबसे ज्यादा पीपल के पौधे लगाए हैं। जुआं, बली कुतुबपुर, चटिया, तिहाड़, जागसी व चरखी दादरी के गांव चंदेली में आक्सीजन बाग लगाए जा चुके हैं।

ये पौधे लगाए

बड़, पीपल, नीम, गुल्लर, हरड़, आंवला, ढाक, मोलसरी, कचनार, जामुन, पिलखन, अर्जुन, चम्पा, जांटी, देसी कीकर, रुद्राक्ष, आम, इमली, सम्भल, शहतूत, बेरी, बेलपत्र, कुसुम, बालम, दाल मोठ, लिसोढ़ा, शीशम आदि। इनके अलावा अन्य औषधिय व छायादार पौधे लगाए गए हैं।

जैविक गेहूं : बंपर पैदावार, मुनाफ़ा अधिक

संगीता शर्मा

किसानी अब पढ़े-लिखे लोगों का काम बन गया है, उच्च शिक्षित व्यक्ति खेती में रोज़गार तलाश रहे हैं। जैविक खेती करके वह उत्पाद के उच्च दाम ले रहे हैं। रेवाड़ी, कोसली के बेरमपुर गांव के प्रगतिशील किसान विक्की यादव इस बात का प्रमाण है। उनका कहना है कि सही तरीके से जैविक खेती की जाए तो किसान एक नौकरीपेशा व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। यह खेती मुनाफ़ा की खेती है।

इज़रायल के बीज की बिक्री

विक्की यादव की ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी थी और पानी क्षारीय था। इसलिए पैदावार न के बराबर थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई व मालामाल हो गए। वह इज़रायल और देसी गेहूं की किस्मों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने इज़रायल के डीजी-19 किस्म के गेहूं के बीज के रूप में गत वर्ष 500 रुपए प्रति किलो (50,000 रुपए प्रति क्विंटल) के हिसाब से बेचे। जबकि इस वर्ष 200 रुपए प्रति किलो (20,000 रुपए प्रति क्विंटल) के हिसाब से बीज बेचेंगे। इसके अतिरिक्त बंसी, अमेरिकन व अन्य देसी गेहूं की जैविक किस्में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं।

अच्छी किस्म की पैदावार

विक्की यादव ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार इज़रायल में रहते थे और उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया कि यहां एक एकड़ ज़मीन पर गेहूं की किस्म डीजी-19 के दो किलो बीज की बिजाई होती है और पैदावार 40 क्विंटल होती है। जबकि भारत के एक एकड़ ज़मीन पर पांच किलो बीज की बिजाई होती है और पैदावार 20 क्विंटल होती है। उन्होंने बताया कि इज़रायल से ऑनलाइन बीज मंगवाए और आधे एकड़ ज़मीन पर बिजाई की व पैदावार 15 क्विंटल हुई। 500 रुपए किलो की दर से बीज को देश के हर राज्य में किसानों को बेचा और किसानों से एक से चार एकड़ ज़मीन में इस किस्म के गेहूं की खेती की है। उन्होंने बताया कि इस किस्म में गेहूं की 100 से 150 बालियां निकलती है और पानी का थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता है। अक्तूबर में बीजाई और अप्रैल के पहले सप्ताह कटाई हो जाती है। विक्की यादव ने बताया कि इस बार एक एकड़ में इज़रायल के किस्म की गेहूं की बिजाई की है और उसे 200 रुपए किलो की दर से बीज के रूप में बेचेंगे। उनका मकसद अधिक से अधिक किसान अच्छी किस्म की गेहूं की पैदावार करें।

गेहूं की होम डिलीवरी

उन्होंने बताया कि उनके पास आठ एकड़ ज़मीन है। पांच साल से जैविक खेती कर रहे हैं और गेहूं व सरसों की जैविक खेती करते हैं। इसके अलावा बाजरा, कपास व तिल की जैविक खेती भी करते हैं। चार एकड़ में सरसों की खेती करते हैं और सरसों प्रोसेसिंग करके 250 रुपए प्रति लिटर की दर से तेल बेचते हैं। उन्होंने बताया कि चार एकड़ ज़मीन में जैविक गेहूं की देसी किस्मों की पैदावार लेते हैं और 5,000 रुपए क्विंटल की दर से बेचते हैं। इसके खरीददार महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली व पंजाब के हैं। इनको होम डिलीवरी करते हैं, जबकि कुछ खरीददार खेतों से गेहूं खरीदकर ले जाते हैं।

जैविक खेती का बड़ा बाज़ार

वह कहते है कि जैविक खेती के उत्पाद का स्वाद व्यक्ति के जीभ को अधिक भाता है। वह इसके लिए कीमत की तरफ़ ध्यान नहीं देता। गुणवत्तायुक्त व रसायनमुक्त चीज खाना आज लोगों की पसंद बन गया है। वह बताते हैं कि प्रतिवर्ष ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो ग्राहक उनके गेहूं खरीदकर ले जाते हैं, वह प्रतिवर्ष उनसे गेहूं खरीद रहा है और साथ ही कई नए ग्राहकों को जोड़ रहा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जैविक खेती का बहुत बड़ा बाज़ार होने वाला है और इसलिए किसानों को रसायनयुक्त खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर मुड़ जाना चाहिए। रसायनयुक्त खेती में अधिक खर्चा, प्रदूषण और सेहत भी ख़राब हो रही है।

मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी

विक्की यादव का कहना है कि जैविक खेती में आरंभ के साल में पैदावार में कमी होती है और तीन साल बाद जैविक खाद व जीवामृत के प्रयोग से मिट्टी पुनर्जीवित हो जाती है और पैदावार बढ़ने लगती है। यादव ने बताया कि जैविक खाद व जीवामृत खुद तैयार करते हैं और फसल के वेस्ट को खेतों में प्रयोग करते हैं, इसके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यादव के खेतों व तकनीकों को सीखने के लिए आए-दिन किसान आते रहते हैं। वह इस बात पर विशेष बल देते हैं कि किसी भी काम को ईमानदारी से किया जाए तो उसका फल दोगुणा अवश्य मिलता है। वह कहते हैं कि 'मैं अपने ग्राहक को पहले प्रोडक्ट सैंपल के तौर पर भेजता हूं और उनको कहता हूं कि आप किसी भी लैब से उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। मैं गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पाद बेचता हूं, कीमत से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता।'

देसी गेहूं अधिक पौष्टिक

विक्की यादव ने जैविक गेहूं 5,000 क्विंटल, काली सरसों को प्रोसेसिंग करके पिछले वर्ष 250 रुपए प्रति लिटर के हिसाब से तेल बेचा। इस बार पीला सरसों लगाया है और यह तेल 450 रुपए लिटर के हिसाब से बिकता है। यह औषधीय तेल और देसी घी के बराबर ताकत देता है। उनका कहना है कि जैविक खेती में भी आजकल लोग गुमराह कर रहे हैं और रासायनिक खेती को जैविक खेती करके बेच रहे हैं। मैं गेहूं के देसी बीज पर काम करता हूं और पुराने बीज में अधिक पौष्टिक तत्त्व होते है और खाने में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। जबकि हाईबीड के बीज में पोषक तत्त्व नहीं होते और स्वादिष्ट कम होते है।

आमदनी में इज़ाफा

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में जैविक मंडी लगती है और किसान वहां जैविक उत्पाद बेचते हैं। दिल्ली में बुधवार व वीरवार जैविक सब्जी व उत्पाद बेचने की योजना बना रहे हैं। चंडीगढ़ में भी जैविक उत्पादों की अच्छी बिक्री हो रही है। इसके अतिरिक्त अधिकतर किसान डायरेक्ट ही जैविक उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। वह कहते है कि किसान किचन वेस्ट और फसल की वेस्ट से जैविक खेती करके लागत को कम कर सकता है। एक एकड़ ज़मीन में वैसे गेहूं की 20 क्विंटल पैदावार होती है, लेकिन जैविक खेती में यह 30 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। जैविक खेती से उत्पाद के दाम तो दोगुणा मिलते ही हैं, साथ में पैदावार अधिक होने से आमदनी बढ़ जाती है।

प्रदेश की मार्किट कमेटियों में किसानों के लिए विश्राम गृह, पीने का पानी, सीवरेज, बिजली, शौचालय आदि की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आवश्यकतानुसार नए भवनों का निर्माण भी करवाया जा रहा है।

भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान चंडीगढ़ के पंचकूला स्थित शोध केंद्र में जल संचयन भंडारण एवं भूजल रिचार्ज पर भी काम किया जाता है। इससे भूमि का जल स्तर भी ऊपर उठेगा और कॉलोनियों को पीने योग्य पानी भी दिया जा सकेगा।

लाइलाज नहीं टीबी, उपचार कराएं

ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) एक जीवाणुजनित रोग है इस जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम से जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवाणु से प्रभावित है और जीवाणु से ग्रसित व्यक्ति के खांसते, बोलते या छींकते समय उसके मुंह से निकले छींटे कोई अन्य व्यक्ति अवशोषित करता है तो वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। हालांकि टीबी रोग का प्रसार किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होता है। सही समय पर टीबी के लक्षणों को पहचानने व उसके उपचार से बीमारी को खत्म किया जा सकता है।

टीबी के लक्षण-

1. तीन हफ्तों से ज्यादा तथा लगातार खांसी रहना।
2. खांसी के साथ साथ बुखार का आना व ठण्ड लगना ।
3. सीने में दर्द होना तथा खांसी आते समय अधिक दर्द होना।
4. कमजोरी व थकावट रहना।
5. भूख न लगना तथा वजन कम होना।
6. रात में तथा सोते समय अधिक पसीना आना।

उपचार तथा देखभाल-

क्षय रोग यानी टीबी श्वसन सम्बन्धी रोग है जिस कारण यह शरीर के अन्य हिस्से जैसे हड्डियां, मस्तिष्क, पेट, पाचन तंत्र, किडनी तथा लिवर को संक्रमित कर सकता है। इस रोग का इलाज डॉक्टर तथा डाइटीशियन की सलाह तथा सुझाव के साथ महीनों तक लगातार चलने वाला इलाज है। टीबी के इलाज के दौरान कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं मरीज को दी जाती हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु को नष्ट तथा नियंत्रित करती हैं। साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक दवा भोजन तथा भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। फलस्वरूप भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का अवशोषण तथा चयापचन (अब्सॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज़म) नहीं हो पता है और इलाज के दौरान मरीज कुपोषित होने लगता है और कुपोषण ज्यादा बढ़ने पर वजन कम, खून की कमी जैसी अन्य समस्याएं इलाज की अवधि पूरा करने में समस्या उत्पन्न करती हैं।

अंबाला के सिविल सर्जन डा. कुलदीप ने बताया कि टीबी के उन्मूलन के लिए हरियाणा सरकार काफी कदम उठा रही है । उन्होंने बताया कि टीबी का उपचार सभी राजकीय चिकित्सालयों में मुफ्त किया जाता है। विभाग की ओर से सभी मरीजों को 6 से 9 माह की दवाई मुफ्त दी जाती है तथा इसके साथ साथ मरीज को प्रति माह 500 रुपए अच्छी खुराक के लिए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं वालंटियर या कोई भी किसी टी बी के मरीज को अस्पताल लेकर आता है तो उन्हें भी 500 रुपए का पारितोषिक दिया जाता है। उन्होंने कहा यदि किसी को लगातार दो महीने से ज्यादा खांसी हो, बुखार रहता हो या शरीर में दर्द रहता हो तो उन्हें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवानी चाहिए। यह रोग लाइलाज नहीं है।

-संवाद ब्यूरो

खेल नीति से अधिक पदक आने की उम्मीद

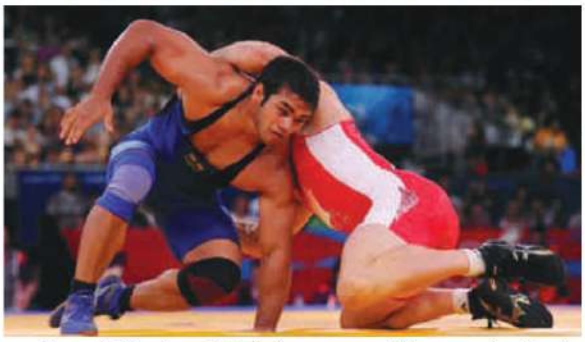

हरियाणा भले ही देश की आबादी की दृष्टि से मात्र 2 प्रतिशत हिस्सा रखता हो लेकिन यहां खेलों में पदक लेने वालों की संख्या करीब 32 प्रतिशत है। नई खेल नीति के चलते प्रदेश में विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चे खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खेलों में अब हरियाणा मेडलों की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। बात ओलंपिक की हो या कॉमनवेल्थ की प्रदेश के पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके पिछले एक दशक में अच्छे खासे मेडल जीते हैं। स्थिति यह हैं कि प्रदेश में खेलों का वातावरण बन रहा है। ओलंपिक व एशियाड में मिली कामयाबी बताती है कि राज्य के खिलाड़ियों में जीत की भूख लगातार बढ़ रही है।

हरियाणा में खेल पुरानी परंपरा है पहले यहां कुश्ती व कबड्डी खेल ही देहात में खेले जाते थे। तरीका पुराना था लेकिन अब धीरे-धीरे इसमें बदलाव हुआ है। कुश्ती गद्दों पर होने लगी व हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर पैर जमा चुकी है। खिलाड़ियों में प्रोफेशनल सोच दिखाई देने लगी है जिसका परिणाम यह है कि नकद इनाम व पद पाने की होड़ मे हरियाणा नंबर वन बन गया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां राज्य सरकार ने खेलों के सेंटर बनाये हैं। भिवानी जहां मुक्केबाजी का हब बनता जा रहा तो सोनीपत कुश्ती व हिसार-सिरसा हॉकी में बुलंदियों को छू रहा है। सरकार ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मैट व जिम उपलब्ध कराए हैं जिनका लाभ लेकर खिलाड़ी अलग अलग प्रतिभाओं में नाम रोशन कर रहे हैं। नई खेल नीति के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईपीएल की तर्ज पर खेल प्रशिक्षकों को ज्यादातर स्थानों पर नियुक्त किया गया है।

प्रदेश में खिलाड़ियों को लगातार मिल रही कामयाबी का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत व हौसले को जाता है। राज्य में यह तभी संभव हो पाया है जब सरकार ने खेलों में बड़ा योगदान दिया। गौर से देखें तो हरियाणा में खेल का कल्चर धीरे -धीरे बढ़ोतरी पर है।

योगेश्वर, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, मौसम खत्री के बेहतरीन प्रदर्शन से आज हरियाणा कई खेलों में भी सिरमौर बना है। मुक्केबाजी में भी लड़कियां चमक रही है। हॉकी व कबड्डी में प्रदेश की लड़कियां अपना लोहा मनवा रही हैं।

खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि खेल नीति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। इसके बावजूद इसमें बदलाव अथवा संशोधन की प्रक्रिया जारी है। पदक विजेता खिलाड़ियों को एचसीएस व एचपीएस लगाने की बजाय विभाग में ही नये पद सृजित करके एडजस्ट किया जाएगा। सरकार खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की पक्षधर है।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

आदर्श गांव खुर्दबन

गांव आदर्श बने, पंचायत में जन भागीदारी बढ़े, इस उद्देश्य से युवराज प्रोफेसर से सरपंच बने। यमुनानगर जिले के गांव खुर्दबन को तीन नेशनल अवार्ड और प्रदेश सरकार की सिक्स स्टार रेटिंग से नवाजा गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी को सराहा। गांव खुर्दबन ने प्रदेश में आदर्श पंचायत का प्रतिमान स्थापित किया है।

विगत चुनाव में गांव खुर्दबन के ग्रामीणों ने युवा सरपंच युवराज को चुना। युवराज इंजीनियर है और अध्यापन कार्य का अनुभव है। पंचायत बनने के बाद उनके लिए पहला कार्य जन-भागीदारी सुनिश्चित करना था। खासकर युवाओं और महिलाओं को पंचायत के कार्यों में आगे लाना। कार्य आसान नहीं था किन्तु सरपंच युवराज ने कर दिखाया। सबसे पहले गांव में दो एकड़ मे पार्क बनवाया। ताकि सुबह-शाम सैर व व्यायाम द्वारा महिलाएं स्वस्थ रह सके। सभी के लिए समय निर्धारित किया गया। गांव में एक इंडोर व्यायामशाला बनाई गई। जिसमें महिला और पुरुष दोनों तय समय में जाते हैं। व्यायामशाला में ट्रेनर रखा गया।

गांव में एक रेस्टोरेंट है। जिसे 'स्वाद गामा आले' के नाम से चलाया गया। इस रेस्टोरेंट को गांव की बेटी एनआरएलएम (राष्ट्रीय आजीविका मिशन) के साथ मिलकर चलाती हैं। ग्रामीण रेस्टोरेंट में परंपरागत और आधुनिक व्यंजन के स्वाद चखते हैं। इसमें गांव के पांच लोगों को काम भी मिला। सरपंच युवराज बताते हैं वैसे तो प्रत्येक पंचायत में गली-नालियों पर कायाकल्प किया जाता है। किन्तु रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आज तक कम कार्य हुआ है। खुर्दबन पंचायत ने उक्त तीनों कार्य पर काम किया। उन्होंने बताया कि पंचायत द्वारा मॉडर्न आंगनवाड़ी प्ले-वे स्कूल की तर्ज पर बनाई गई। जिसमें बालकों के खेलने और सीखने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं पंचायत ने उपलब्ध कराई हैं।

गांव खुर्दबन की हर गली पक्की है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। शादी-विवाह के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया गया। जिसे हर ग्रामीण परिवार मामूली खर्च पर उपयोग करता है। सरपंच युवराज ने बताया कि पंचायत का एक और खास कार्य, जिसकी वजह से गांव को प्रसिद्धि मिली। गांव में बैडमिंटन हॉल है। जो 3600 स्कवायर फिट में बना है जिसमें गांव व दूसरे गांव के खिलाड़ी खेल का अभ्यास कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

खुर्दबन पंचायत को राष्ट्रीय स्तर के तीन अवार्ड मिले हैं और प्रदेश सरकार की सिक्स स्टार रेंकिग के लिए नवाजा गया है। कोरोना काल में मनरेगा स्कीम के तहत पांच हजार कार्य दिवस लगे, जिसमें 200 ग्रामीणों को काम मिला।

-मनोज चौहान

जीवन में पानी का बहुत महत्त्व है इसलिए हम सभी को पानी का आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम पानी वाली फसलों को उगाने पर बल देना चाहिए।

राज्य सरकार ने एक समर्पित 'उद्यमी और स्टार्टअप नीति' बनाई है जो बेहतर अवसंरचना और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने पर समान बल देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है।

समान विकासः कहीं उद्घाटन तो कहीं शिलान्यास

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बजट सत्र के तुरंत बाद प्रदेश के चहुंमुखी विकास की ओर कदम बढ़ाया है। जिला स्तर पर स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने अनेक परियोजनाओं की न केवल आधारशिला रखी बल्कि अनेक परियोजनाओं को उद्घाटन भी किया।

जींद को 145.73 करोड़ रुपए की परियोजनाएं

जींद के लिए 145.73 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। 27.82 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और 117.91 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

रोहतक के लिए 18 परियोजनाएं समर्पित

मनोहरलाल ने रोहतकवासियों को 132 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने 24.12 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 107.89 करोड़ रुपए की दस परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

फतेहाबाद में 52 करोड़ से होंगे विकास कार्य

फतेहाबाद की जनता को 52.59 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इनमें 27.53 करोड़ रुपए की दस परियोजनाओं का उद्घाटन और 25.06 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं की आधारशिला है।

सिरसा के विकास के लिए 11 परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने सिरसावासियों को 41.96 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने 22.25 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 19.71 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

नूह को मिली 16.55 करोड़ रुपए की दस परियोजनाएं

नूह जिले में 16.55 करोड़ रुपए की दस परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इनमें आयुष विंग केंद्र, फिरोजपुर झिरका, बाई में पीएचसी, तावडू खण्ड के विभिन्न स्कूलों में 36 अतिरिक्त कक्षा कक्ष (एसीआर), पुन्हाना खंड के विभिन्न स्कूलों में 79 एसीआर, जीएचएस टपकण का उन्नयन, जीएसएसएस मेओली कलां में नौ एसीआर, जीएचएस मंडीखेड़ा, नगीना में आठ एसीआर, और नूह, फिरोजपुर झिरका व पिंगांव में तीन बाल भवन शामिल हैं।

रेवाड़ी को मिली आठ परियोजनाएं

मनोहर लाल ने रेवाड़ीवासियों को 117.42 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं को समर्पित की हैं। उन्होंने 87.12 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं का उद्घाटन और 30.30 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

सोनीपत में 47.58 करोड़ रुपए के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने मनोहरलाल ने सोनीपतवासियों को 47.58 करोड़ रुपए की सात परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने 4.70 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और 42.88 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

भिवानी में सड़कों का निर्माण

मनोहर लाल ने भिवानी जिले में 9.88 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें बैराण से बुढ़ेड़ा, देवसर से बजीणा, बलियाली से सागवन, कुंगड़ से सुंदर नहर वाया पुर सिवाड़ा खेड़ी सड़क, टिटाणी से लहलाना और रोढ़ा से सिधनवा सड़क का शिलान्यास शामिल है।

चरखी दादरी में 25.53 करोड़ रुपए की छह परियोजनाएं

चरखी दादरी को 25.53 करोड़ रुपए की छह परियोजनाएं मिली हैं। सीएम ने 19.45 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और 6.08 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

कैथल के विकास के लिए 21 करोड़

मुख्यमंत्री ने कैथलवासियों को 20.84 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं को समर्पित किया है। उन्होंने 17.59 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं का उद्घाटन और 3.25 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास किया। उद्घाटन परियोजनाओं में राजौंद में नवनिर्मित नगर पालिका कार्यालय भवन, राजौंद में निर्मित शॉपिंग कॉम्पलैक्स, पूंडरी में बुर्जी नम्बर 166844 सिरसा ब्रांच, पूंडरी में इंडोर-आउट डोर स्टेडियम, गांव क्योड़क में कोटी-कुटेश्वर तीर्थ का जीर्णोद्धार शामिल है। कैथल की नई अनाज मंडी में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शैड व ऑफिस कॉम्पलैक्स किसान रैस्ट हाउस का शिलान्यास भी किया।

कुरुक्षेत्र में 43.02 करोड़ से होंगे विकास कार्य

कुरुक्षेत्रवासियों को 43.02 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। इनमें 33.98 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं का उद्घाटन और 9.04 करोड़ रुपए की दो परियोजनाओं का शिलान्यास है।

पानीपत के लिए छह परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने पानीपत को 59.85 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं को समर्पित किया है। तीन करोड़ रुपए की लागत से गांव गढ़ी छजू में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 56.85 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें गांव बापोली, चुलकाना और राणा माजरा में जल आपूर्ति का विस्तार और सीवरेज योजना प्रदान करना, गांव भालसी, इसराना में नए स्टेडियम का निर्माण, गांव वैसर, इसराना में नया स्टेडियम का निर्माण, पानीपत (जीटी रोड एनएच -44) धरौपती एनएच-709 का 4 लेनिंग का कार्य शामिल है।

करनाल को मिली 15.72 करोड़ रुपए की पांच परियोजना

करनाल जिले के लिए 15.72 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनमें कमालपुरा में सामुदायिक केंद्र, खण्ड निसिंग के गांव जांबा में स्टेडियम, सेक्टर-16 में सामुदायिक केंद्र भवन, गांव बरसात में आवासीय क्वार्टर सहित पीएचसी का निर्माण और जुंडला में 33 केवी सब स्टेशन शामिल है।

गुरुग्राम के विकास के लिए पांच परियोजना

गुरुग्राम जिले के लोगों को 72.72 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं की सौगात मिली है। इनमें 18.13 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं का उद्घाटन और 54.59 करोड़ रुपए की दो परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

पलवल को मिली पांच परियोजना

पलवल जिला के पांच गांव औरंगाबाद, दीघोट, भिडूकी, सौदहंद व खांबी में महाग्राम योजना के तहत सीवर बिछाने व पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी के कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों पर 88.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

हिसार में 87.71 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य

हिसार जिले के लोगों को 87.71 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाएं मिली हैं। इनमें 78.67 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 9.04 करोड़ रुपए की दो परियोजनाओं का शिलान्यास है।

झज्जर को मिली 332.34 करोड़ रुपए की तीन परियोजना

झज्जर जिले के लोगों को 332.34 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। इनमें 27 करोड़ रुपए की दो परियोजना का उद्घाटन और 305.34 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। उद्घाटन परियोजनाओं में झज्जर कोसली सड़क (एसएच -22) क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण और किला मोहल्ला, बहादुरगढ़ में सामुदायिक केंद्र शामिल है।

पंचकूला, यमुनानगर को दो-दो परियोजना

मुख्यमंत्री ने पंचकूला, यमुनानगर जिले को 42.41 करोड़ रुपए की दो-दो परियोजनाओं को समर्पित किया। पंचकूला में 4.83 करोड़ रुपए की लागत से खंगेसरा से जसवंतगढ़ तक लिंक सड़क का उद्घाटन तथा एमडीसी, सेक्टर-6, पंचकूला में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।

महेंद्रगढ़, अंबाला और फरीदाबाद को मिली एक-एक परियोजना

मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़, अंबाला और फरीदाबाद के लिए 59.19 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें अंबाला जिले में 27.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित छप्पर-अधोया सड़क पर गांव कूलपुर में अंबाला-सहारनपुर सेक्शन पर दो लेन आरओबी का उद्घाटन तथा महेंद्रगढ़ के गांव सिहमा में 17.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास और जिला फरीदाबाद में सेक्टर-59 में 13.84 करोड़ की लागत से 66 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास शामिल है।

-संवाद ब्यूरो

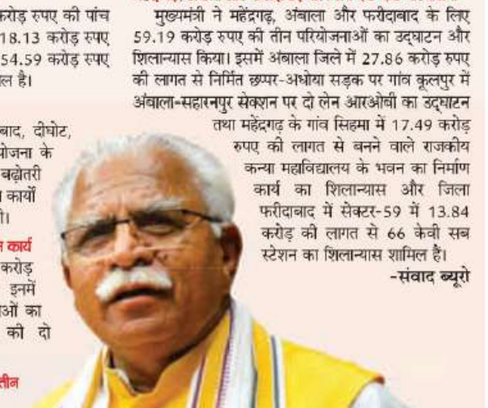

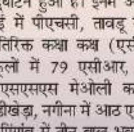

सरकार नेटवर्क सुरक्षा और डेटा संरक्षण सहित साइबर सुरक्षा पर अधिक बल देते हुए सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए तहसीलों, उप-तहसीलों एवं खंडों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

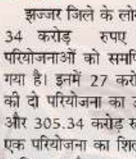

पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक्स सेवाएं हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के लिए तीन बायो सेफ्टी लेवल-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

आस्था का मेला

प्रदेश में समय समय पर लगने वाले मेले यहां की समृद्ध संस्कृति को रेखांकित करते हैं। मेला शब्द का निर्माण मिलन से हुआ है। मिलन यहां की परंपरा है, यहां का जीवन है। सच मानो तो यहां की लोकसंस्कृति में मिलने के बहाने रचते-बसते हैं। जन-जीवन में सौहार्द की भावना अटूट बनी रही इस लिए यहां की संस्कृति में तीज-त्योहार व मेलों का विशेष महत्व है। इन अवसरों पर कुटूंबजन एक दूसरे से मिलने के लिए दूरदराज से भी अपनों के पास चले आते हैं।

आधुनिकता के नाम पर यहां की मूल संस्कृति प्रभावित अवश्य हुई है लेकिन असंख्य परिवार आज भी इन अवसरों पर एकत्र हो खुशियां मनाने से चूकते नहीं हैं। शायद यूं ही नहीं कहा गया है - देशोस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्यां स्वर्गः सन्निभः।

हरियाणा के कुछ मेले तो राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हैं। उदाहरणार्थ सूर्यग्रहण के अवसर पर लगने वाला कुरुक्षेत्र का मेला विश्व में बेजोड़ है। यहां लगने वाले मेले कई प्रकार के हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध देवी-देवताओं से है तो कुछ का सम्बन्ध उत्सव एवं त्यौहारों से है। कुछ सिद्धों एवं महात्माओं से संबंधित हैं तो कुछ पीर-पैगम्बरों से। कुछ मेले तो मात्र तिथियों की पावनता, पवित्रता एवं महत्व को ही दर्शाते प्रतीत होते हैं।

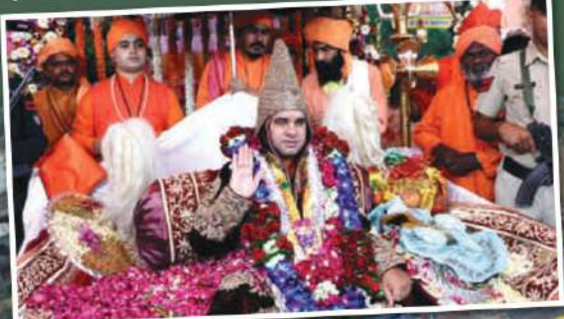

फाल्गुन माह की नौवीं को रोहतक के अस्थल बोहर व गांव रभड़ा में सिद्ध एवं नाथ महात्माओं के नाम पर मेले आयोजित हुए। इनकी मान्यता पूरे देश में है। इस प्रकार के मेले बाबा जमनादास भालौट, बाबा हिम्मतनाथ नाहरी, बाबा मोहनदास लहरड़ा, बाबा जिंदा मोई, बाबा नागा नवां राजगढ़ में लगते हैं।

बोहर में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में लगे मेले में खूब रौनक रही। रैबारी समाज ने बाबा मस्तनाथ के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। शरीर पर भस्म रमाए नागा साधु नाचते गाते नजर आए। मठ के महंत बालकनाथ योगी ने आरती की। हजारों श्रद्धालुओं ने समाधि पर माथा टेककर मन्नतें मांगी। मेले में नाथ संप्रदाय से जुड़े हजारों साधु, संत व पीरों का आगमन हुआ।

मठ परिसर में बड़े-बड़े झूले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। खिलौने, शृंगार, खाने-पीने के सामान की स्टालें सजी रही। मेला प्रबंधन समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया।

सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ की स्मृति में लगे मेले का अपना इतिहास है। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा मस्तनाथ मठ में श्रद्धालु समाधि स्थल व धुने पर माथा टेक कर मन्नत मांगते हैं। इसके साथ ही बाबा की समाधि पर गुड़ व काला कंबल चढ़ाकर पूजा की जाती है।

मेला परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच समाधि स्थल से कुछ दूर रखा बंचारी का नगाड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहां लगातार नगाड़े की थाप पर श्रद्धालु झूमते रहे।

बाबा मस्तनाथ (1764) एक हिंदू संत थे। उनका जन्म रोहतक जिले के कसरेटी गांव में हुआ था। उनको गुरु गोरक्षनाथ जी के पुर्नजन्म की मान्यता है। 2012 में उनके सातवें शिष्य महंत चांदनाथ ने उनके नाम पर अस्थल बोहर स्थित मठ प्रांगण में बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की।

मठ के महंत योगी बालकनाथ मेले के अंतिम दिन राजशाही पोशाक में गद्दी पर विराजमान हुए। योगियों व श्रद्धालुओं ने सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के रूप में उनके दर्शन किए। इस अवसर पर आयोजित दंगल आकर्षण का केंद्र रहा। सोमवीर पहलवान ने एक लाख 52 हजार रुपए का कुश्ती दंगल जीता।

-मनोज प्रभाकर

पनघट की अनूठी संस्कृति

लोकसाहित्य और कुओं में परस्पर गहरा नाता रहा है। देहात में कुएं से जुड़ी असंख्य ऐसी कहानियां, लोककथाएं, पहेलियां, मुहावरे तथा घटनाएं आज भी हरियाणवी संस्कृति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुआं पूजणां, कुएं मैं पड़णा, कुएं धोरै चक्कर काटणां, आग्गै कुआं पाछै खाई, कुआं बेगाणां, कुएं का ब्याह, कुएं झेरे मैं पड़णा असंख्य ऐसे मुहावरे हैं, जो आज भी जनमानस की सहज बातचीत का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, बांध भरोट्टा नीर का, दे पाथर का जूण, बांधण आला बांधग्या, खोल्लण आला कौण, जैसी जकड़ी का भी उत्तर कुआं ही है। इतना ही नहीं, पणघट जात्तै, पण घटै यही कहै सब कोय, पणघट जा नहीं पण घटै जो घट मैं पण होय, जैसी रहस्यवादी कहावतें भी कुएं से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणवी लोकजीवन में मान्यता है कि आदमी को आदमी तो फिर मिल जाता है, पर कुएं को कुआं नहीं मिलता, कहा भी गया है- गया गांव जहां चौधरी हंस्या, गया रूख जहां बुगला बस्या, गया ताल जहां उपजी काई, गया कुआ जहां भई हथाई अर्थात् जिस गांव का मुखिया मज़ाकिया हो, जिस पेड़ पर बगुला बैठने लगे, जिस जोहड़ में काई लग जाए और जिस कुएं की तली बैठ जाए, तो उक्त संपदा नष्ट हो जाती हैं।

लोकजीवन में हरियाणवी महिलाएं गीतों के माध्यम से अपनी मनोभावनाओं को उजागर करती हुई सहज ही गाती हुई देखी जा सकती हैं कि मेरा डोल कुएं मैं लटकै सै, मेरी पोरी-पोरी मटकै सै, मेरा झिलमिल करै शरीर, परे सी ना होह्लै नै। इतना ही नहीं, हरियाणवीं लोक संस्कृति में कुएं से रस्मों-रिवाजों, परम्पराओं से परस्पर गहरा नाता है। लोकसमाज में महिलाओं द्वारा छोरों के जन्म के समय ग्यारह, इक्कीस अथवा चालीस दिन पूरे करने के पश्चात् कुआं पूजने की परम्परा आज भी विद्यमान है। इस अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाएं कुएं पर जल-पूजने के लिए ले जाती हुई अक्सर महिलाएं यह गीत गाती - ससुर मैं कुएं पै जल पूज्जण जाउंगी, लहंगा पहन ओढ़ू सिर पै चून्दड़ी, करकै सोलह शृंगार जल पूज्जण जाउंगी। इतना ही नहीं, मेरे सिर पै बंटा टोकणी, मेरे हाथ मैं नेज्जू डोल, मैं पतली सी कामणी, हुई मैं नीर भरै थी, दयानन्द नै घोड़ा डाट्या ए, पिया मैं कुएं तै पाणी खींचू मेरे गात मैं झटकै लाग्गै, मेरा पतली अकल खावै ओ, आदि गीतों में कुएं की संस्कृति की साक्षात् अभिव्यक्ति देखने को मिलती है।

इतना ही नहीं, कंध का दाम्मण, लाल चून्दड़ी, धौली कुरती, मड़कण घाली जूती तथा कड़ी छलकते म्हैरी पाती व रमझोल की झरण-झरण के साथ जब नई नवेली दुल्हन कुएं पर पानी भरने के लिए निकलती है, तो अल्हड़ युवा भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते उनकी प्रतिक्रियाओं को देख नई दुल्हन भी इस गीत के माध्यम से कुछ यूं कह उठती है कि ,मेरा कंध का दाम्मण लाल चूंदड़ी जाले की, छोर्या नां मारी किलकारी, बहू रै आई कालै की, मैं कुए तै पाणी ल्याई छोरया नैं बोली मारी, बहू रै या काले की।

हरियाणवी लोकजीवन में पनघट पर महिलाओं द्वारा बात-बातों में अपने सुख-दुख को बांटने की परम्परा भी है। पनघट पर महिलाओं को सभी की आगे पीछे की रिश्तेदारियों का पता लग जाता था। नई वधु और अन्य युवतियों को साज-सिंगार कर गीत गाते हुए पनघट के कुएं तक जाने का मौका मिला जाता था। आपसी मखौल और हंसी ठट्ठों में घरेलू माहौल का बदलाव हो जाता था। जच्चा लड़का होने पर गीत गाने कुएं का पूजन जाती है। ये दीवाली के अवसर पर कुएं की मेड़ पर दीपक जलाती थीं। कहीं कोई महिला सहेली का बंटा टोकना उठवाने में हाथ बंटवा रही है, तो कोई पैड़ियों से ही आंगतुकों का स्वागत कर रही है। महिलाएं घर में चाहे किसी भी तरह के कपड़े क्यों न पहनती हो, किन्तु पनघट पर अच्छी तरह श्रृंगार करके ही जाती हैं। पहले तो नई-नवेली दुल्हनें घाघरा पहन, सितारों - गोटों से युक्त चूंदड़ी ओढ़, पैरों में कढ़ाई की हुई डिजानदार जूतियां व ऊपर से नीचे तक गहनों से सज-धज कर पास-पड़ौस की आठ या इससे अधिक महिलाएं एकत्रित होकर गीत गाती हुई पानी लेने जाती रही हैं। सास की पीड़ा भी गीतों में देखने को मिलती है। जैसे -

खिल रहा चांद लटक रहे तारे,
चल चन्द्रवाल पाणी
सासड़ की जाई मेरी नणंद हठीली रात नै खन्दा दई पाणी।

हरियाणा में कुओं पर स्नानघाट तथा छत्तरियां बनाने की परम्परा रही है, ताकि कुएं पर महिलाएं एकांत में स्नान कर सकें और छत्तरियों से पानी की स्वच्छता विद्यमान रहे। कुओं से घरों तथा स्वच्छ पानी की नालियां व कुओं के साथ पशुओं के लिए खेल आदि बनाने की परम्परा भी रही है, ताकि जन-मानस एवं पशु-पक्षी नैसर्गिक जल का आनन्द ले सकें। चूने तथा लखौरी ईंटों से बनने वाले कुएं के उपर लोकसांस्कृतिक चित्रों की झलक भी देखने को मिलती है। देवी-देवताओं के चित्रों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक एवं पौराणिक घटनाओं के भित्ति-चित्र कुएं की लोकसांस्कृतिक छटा को निखारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

-महासिंह पूनिया

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com